

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 02/23

वर्ष 2023

जीसीएमएस संख्या 2023/25

बउनवानी:-हुकमचन्द पुत्र श्री छीतरमल कोली, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टिकल रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976) उपस्थित:-श्री रंगलाल गुर्जर

श्रीमति पूजा मीना (प्रवर्तन निरीक्षक)

वकील अपीलान्त

पैरोकार रसद

:-निर्णय :-

दिनांक:- 23.01.2024

यह अपील अपीलान्त द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 01.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पों. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्त एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। यह तर्क भी दिया कि उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 7.4.2017 को अपीलान्त की दुकान की जॉच की गयी। दौराने जॉच रसद सामग्री के गबन एवं दुरुपयोग जैसा कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है केवल मात्र तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया किन्तु नोटिस की प्रति प्रार्थी से गुम हो जाने के कारण प्रार्थी कारण बताओ नोटिस का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका बिना जवाब के प्रार्थी को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी की दुकान के अनुज्ञा पत्र को अत्यधिक कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया जो कतई गैर कानूनी है। यह तर्क भी दिया कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 2.6.2017 मे सभी प्रकार के आरोप तकनीकी प्रकृति के आरोप है कोई राशन सामग्री गबन अथवा कालाबाजारी या दुरुपयोग किये जाने का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के परिपत्र दिनांक 25.3.1994 मे दिये गये निर्देशों के विरुद्ध जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 1.9.2017 पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना साबित नहीं होता है जबकि आदेश दिनांक 1.9.2017 मे यह लिखा गया है कि प्रार्थी को कई बार सुनवायी एवं जवाब पेश करने हेतु लिखा गया है एवं डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब का समग्र अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं बताया गया है किन्तु दूसरी तरफ जवाब प्रस्तुत नहीं करना बताया गया है इस प्रकार बनावटी शब्दों का प्रयोग आदेश जैर अपील मे किया गया है जो सरासर गलत है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार को दिये गये नोटिस एवं नोटिस के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत जवाब की प्रति संलग्न नहीं है। उक्त दुकान अपीलान्त का एक मात्र रोजगार का साधन है जिससे अपीलान्त के परिवार का पालन पोषण होता है किन्तु उक्त दुकान के अभाव मे अपीलान्त के सामने परिवार का पालन पोषण की भारी समस्या है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे की गयी थी जो क्षेत्राधिकार मे नहीं होने के कारण दिनांक 27.1.2023 को खारिज करते हुए श्रीमान के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गयी है। माननीय न्यायालय के निर्णय से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। क्योंकि यह अपील मयाद बनाए गए की गयी है साथ ही यह भी तर्क दिया कि श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त राज0 जयपुर के पत्रांक/ (1)खा.वि./

.....(1).....

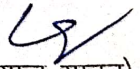
(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सत/सवाईमाधोपुर/17-ए जयपुर दिनांक 10.3.2017 व जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक स्पे. 1 दिनांक 5.4.2017 के क्रम में दिनांक 6.4.2017 से 7.4.2017 तक की अवधि में संयुक्त जॉच दल द्वारा उनको आवंटित खण्डार तहसील के 5 उचित मूल्य दुकानदार श्री गोवर्धन गर्ग, अल्लापुर, श्री दिनेश मीना, दौलतपुरा, श्री विनोद सिंह राजावत मेईकला, श्री हुकमचन्द कोली बहरावण्डा कलां एवं श्री सतीश कुमार जैन खण्डार की दुकानों का निरीक्षण किया गया। दौराने जॉच अपीलान्ट की दुकान बन्द पायी गयी, दुकान के बाहर दुकान बन्द होने का कोई कारण अंकित नहीं पाया गया। दुकान के बाहर मूल्य स्टोक सूची बोर्ड पर सूचनाओं का प्रदर्शन अंकित नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार को सूचना दिये जाने के बावजूद दुकान नहीं खोलना एवं राशन सामग्री का नियमित रूप से वितरण नहीं करना एवं बिना सक्षम अनुमति के वितरण केन्द्र में परिवर्तन किया जाना पाया जाने पर अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया जाकर अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जरिये पत्रांक 1878-79 दिनांक 2.6.2017 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके उपरान्त अपीलान्ट को कई बार सुनवायी एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु अपीलान्ट डीलर द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री हुकमचन्द कोली का प्राधिकार पत्र मय प्रतिभूति राशि 1000/-रु समपहरण किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार श्री हुकमचन्द कोली, उचित मूल्य दुकानदार को जारी नोटिस क्रमांक 1878-79 दिनांक 2.6.2017 का जवाब नहीं दिया गया एवं इसके अतिरिक्त सुनवायी हेतु डीलर को कई बार लिखा जाने पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत आदेश जैर अपील में यह भी अंकित किया गया है डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब का समग्र अवलोकन कर युक्तियुक्त सुनवायी की गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील निर्णय दिनांक 1.9.2017 में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने के संबंध में किये गये कथन विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस क्रमांक 1878-79 दिनांक 2.6.2017 की प्रति है परन्तु उक्त नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है एवं उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब की प्रति उपलब्ध नहीं है और ना ही पत्रावली की आदेशिका संघारित की गयी है। उक्त विवेचन से यह भलि भांति स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, और बिना सुनवायी के पारित निर्णय विधिसम्मत होने की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप भी विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 के निर्देशों अनुसार तुच्छ आरोपों की श्रेणी में आते हैं जिसके आधार पर डीलर के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट डीलर को पुनः सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट डीलर को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर